

ज्ञान के संबंध में मार्गदर्शन जारी करने का है ; जी०

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्रों (श्री जनार्दन पृथ्वारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) . कटिहार जिले में किसानों द्वारा बैंकों को दिये गए प्रत्येक आवेदन के जारों के संबंध में, सूचना जिस रूप में मांगी गई थी, वह उस रूप में इकट्ठी नहीं की जाती । अबलत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिये हैं कि छोटे ऋण आवेदनों को 3 से 4 गप्ताहों की अवधि के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए । बैंकों को यह निर्देश भी दिये गए हैं कि वे अपने शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त अधिकार सौंप दें जिससे कि 80 प्रतिशत आवेदनों को शाखा-स्तर पर ही निपटाया जा सके । भारतीय रिजर्व बैंक के ऋणों का अनुपालन न किये जाने के किसी भी मामले की सूचना मिलने पर, रिजर्व बैंक और संबंधित बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उस मामले की जांच की जाती है तथा उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं । हाल ही के उपलब्ध जिले-वार आंकड़ों से पता चलता है कि दिसम्बर, 1980 की स्थिति के मुताबिक कटिहार जिले में उन खेतों की संख्या, जिनमें बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजनों के वास्ते ऋण दिये गए थे, 7605 थी और ऐसे खेतों में ऋणों की बकाया राशि 1.99 करोड़ रुपये थी ।

Export of Fish from Orissa

2285. SHRI RASA BEHARI BEHERA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the figures of export of fish from Orissa to foreign countries during the year 1982-83 from sea fishing and sweet water fishing ;

(b) what are the radical measures being taken to promote export trade from Orissa sea fishing and sweet water fishing ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : (a) Export of marine products through Paradeep Port in Orissa during April—December 1982 amounted to Rs. 13.59 crores. Export figures in respect of sweet water fish are not available.

(b) and (c) Steps being taken to promote export of marine products from Orissa as from the rest of India, include chartering of deep sea fishing vessels, prawn farming, participation in specialised trade fairs overseas, publicity through overseas press, product and market diversification through Trade Promotion Offices abroad, seafood delegations, Indian Seafood Trade Fair etc.

Institutional credit for Rural Development

2286. SHRI RASA BEHARI BEHERA : Will the Minister of FINANCE pleased to state :

(a) whether Government have chalked out any programme with State Governments to meet the need for provision of adequate and timely institutional credit for more development and also stress the need for supervised credit system with organisational efficiency aimed at the benefit of weaker sections ;

(b) if so, what are the actual achievements made so far ;

(c) is it a fact that identification of beneficiaries, avocations and viable schemes, timely and expeditious disposal of applications for loans in